

महत्वपूर्ण एवं खास

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक करेंगे धमतरी और गरियाबंद जिले में निर्माणाधीन कार्यों का परीक्षण

रायपुर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में निर्माणाधीन लकीरगाँव के परिषद के लिए माह अप्रैल 2025 में राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक आएंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण अवसरचना विकास एजेंसी, नई दिल्ली के निरीक्षण कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक सुशील कुमार पण्डित धमतरी एवं गरियाबंद जिले का दौरा करेंगे। उनका मोबाइल नंबर +91-9419186625, और +91-9797490901 है। सड़क निर्माण से संबंधित शिकायतें उन्हें मोबाइल नम्बर पर साझा की जा सकती हैं।

केनरा बैंक में लाखों के म्युल एकाउंट से लाखों के लेनदेन खुलासा

भिलाई-रायपुर (आरएनएस)। शहर के केनरा बैंक की वैशालीनगर ब्रांच में म्युल अकाउंट (फर्जी लेनदेन खातों) से जुड़े एक बड़े साइबर फ्राँड का खुलासा हुआ है। बैंक की आंतरिक जांच में सामने आया कि कुल 111 खातों में 87.60 करोड़ रुपए का संधिगत लेनदेन किया गया है जिससे बैंक और प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बैंक मैनेजर की सतर्कता से 22 लाख रुपए की राशि को फ्रीज कर लिया गया है लेकिन बाकी राकम खातों से विडॉर कर ली गई है। इस मामले में केनरा बैंक प्रबंधन द्वारा वैशालीनगर थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है, और पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच के आधार पर आशंका जताई जा रही है कि इन खातों का उपयोग ऑनलाइन सट्टा, मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर ठगी जैसे अवैध गतिविधियों में किया गया है। खाताधारकों की पृष्ठभूमि की भी जांच जा रही है कि कहीं ये अकाउंट्स फर्जी दस्तावेजों के आधार पर तो नहीं खोले गए थे। साइबर एक्सपर्ट्स और बैंकिंग अफसरों की संयुक्त टीम अब इन खातों से जुड़े लेन-देन और ट्रान्जेक्शन ट्रेल की जांच में जुटी है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए बैंकिंग रेगुलेटर्स और साइबर क्राइम सेल को भी अलर्ट कर दिया गया है।

सिविल सेवा दिवस की मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं

रायपुर (आरएनएस). मुख्यमंत्री विष्णु देव सायने ने राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के अवसर पर देश सेवा में समर्पित सभी सिविल सेवकों एवं उनके परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनाएँ दी हैं। मुख्यमंत्री सायने ने कहा कि यह दिन न केवल सिविल सेवकों के अमूल्य योगदान को स्मरण करने का अवसर है, बल्कि यह भविष्य की चुनौतियों के संदर्भ में आत्मसम्यक और नवचिंतन का भी दिवस है। यह अवसर हमें याद दिलाता है कि प्रशासनिक तंत्र राष्ट्र के विकास पथ का मूल आधार है, और सिविल सेवकों की दक्षता, निष्ठा और दूरदृष्टि ही नीतियों को ज़मीन पर पहुँचाने में सहायक होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिविल सेवक वह कड़ी हैं जो सरकार की योजनाओं और जनता की अपेक्षाओं के बीच सेतु का कार्य करते हैं। उन्होंने कहा सिविल सेवकों की प्रतिबद्धता और परिश्रम से ही देश और प्रदेश सुशासन के पथ पर अग्रसर होता है। उन्होंने सिविल सेवकों को निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का वहन करते हुए देश और प्रदेश की उन्नति में अपना बहुमूल्य योगदान देने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि आपकी प्रतिबद्धता एवं कर्मठता ही भारत को एक समर्थ, समावेशी और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की नींव है।

आईईडी विस्फोट में जवान शहीद
बीजापुर-रायपुर (आरएनएस)। जिला - बीजापुर तोयनार- फरसेगढ़ रोड निर्माण में आरएसओ इन्ड्यूटी में लगे 19/सी सीएफ के जवान मनोज पट्टरी उम्र 26 वर्ष इन्ड्यूटी के दौरान प्रेशर आईईडी की चपेट में आने से शहीद हो गए। घटना तोयनार से 4 किमी दूर फरसेगढ़ की ओर जंगल का है। ग्रामीणों को लाभान्वित करना कार्यों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध जवान को निशान बनाना माओवादीओं के एक कार्यतापूर्ण कृत्य है। क्षेत्र में सर्व अभियान लगातार जारी है।

पुलिस ने पकड़ा ज्वलनशील पेट्रोल-डीजल का अवैध भंडारण

रायपुर । आरएनएस

दिनांक 20.04.2025 को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग संगठित होकर मंदिर हसीद स्थित ऑयल डिपो इंडियन ऑयल गुजरा, एचपीसीएल0 मंदिर हसीद से निकलने वाले टैंकरो से पेट्रोलियम पदार्थ (पेट्रोल, डीजल, एथेनॉल) की कटिंग करके अधिक लाभ अर्जित करने की नियत से अपने-अपने अवैध यार्डों में ज्वलनशील पदार्थ (पेट्रोल, डीजल, एथेनॉल) को अत्यधिक मात्रा में संग्रहित करके झुगों में रखे हुए हैं। मुखबिर की सूचना पर शुक्रवार को बनावार नोहरा अमरेश से 04 दीप्तिमंद मंदिर हसीद गुजरा फाटकर भाग पदार्थ की 7210 रूपये,

छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम में सुधार से औद्योगिक विकास को नई दिशा

❑ आध्यात्मिक निवेश और
श्रमिक कल्याण की प्रभावी
पहल

❑ श्रमिकों के लिए कारखाना
परिसर में ही आवासीय सुविधा
का रास्ता खुला

रायपुर

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने और श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। यह संशोधन, जो 27 फरवरी 2025 को अधिसूचित किया

नए कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा छत्तीसगढ़ – मुख्यमंत्री

☐ गृहमंत्री अमित शाह की
 अध्यक्षता में आपराधिक कानूनों पर
 समीक्षा बैठक

❑ गृह मंत्री ने शीघ्र नए क़ानूनों को राज्य में शत प्रतिशत लागू करने पर दिया बल

❑ बैठक में बस्तर के विकास और नक्सल उन्मूलन पर भी हुई चर्चा

रायपुर

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज नई दिल्ली स्थित नॉर्थ ब्लॉक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। शाह की अध्यक्षता आयोजित बैठक में राज्य में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन को लेकर समीक्षा की गई। इसके साथ ही नक्सलवाद के उन्मूलन,

था, औद्योगिक इकाइयों के लिए पट्टे पर ली गई भूमि के उपयोग और औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिक आवास निर्माण को लेकर नए अवसर प्रदान करता है। इस कदम को राज्य की औद्योगिक नीति को और अधिक निवेश-अनुकूल बनाने और स्थानीय श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है।

पट्टे पर दी गई भूमि का 15 प्रतिशत नियमितीकरण

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर किए गए नए संशोधन के तहत औद्योगिक इकाइयों को पट्टे पर दी गई कुल भूमि का 15 प्रतिशत हिस्सा गैर-औद्योगिक गतिविधियों, जैसे प्रशासनिक भवन, कैटीन, या अन्य सुविधाओं के लिए नियमित करने की

डंग से लागू करने में उ

वस्तर के समग्र विकास और राज्य में सुक्ष्म व्यापार तंत्र को और अधिक सशक्त बनाए रखने की चर्चा हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित केन्द्रीय गृह मंत्रालय एवं राज्य सरकार के अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर चर्चा की गई। इसके साथ ही मुद्दिस, जेल, अदालतों, अभियोजन और क्रॉसिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई।

मुख्यमंत्री सायने बैठक में जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रशासनिक व तकनीकी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। राज्य में 27 प्रकार की एसओपी (Standard Operating

नुपुति दी गई है। पहले यह सीमा रख थी, जिसके कारण कई इकाइयों पर परिचालन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब इस टूट से घटती संपत्ति इकाइयों की कार्यक्षमता बढ़ाने लिए लचीले ढंग से भूमि का उपयोग कर सके।

औद्योगिक श्रमिक आवास निर्माण ने अनुमति

संशोधन का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू नैयौद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए आवास निर्माण की अनुमति है। यह नवम न केवल श्रमिकों को बेहतर रहन-सहन की सुविधा प्रदान करेगा, बल्कि औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों की पलब्धता को भी बढ़ाएगा। इससे मिलने वाले कार्यस्थल के नजदीक रहने का अवसर मिलेगा, जिससे उनकी यात्रा

प्रणी भूमिका निभाएंगे

बैठक में नक्सल समस्या के स्थान समाधान के लिए भी विशेष गणनीति चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल महीनों में राज्य में चलाए गए ऑपरेशनों में कई वांछित नक्सली मारे गए, गिरफ्तार हुए या आत्मसमर्पण कर चुके हैं। किशन नेलानार योजना, बस्तर ओलेफ़िक, महिा सुरक्षा केंद्र, और आदिवासी क्षेत्रों में होमवर्क पर्यटन ढांचे का विकास जैसे प्रयासों

मल और समय की बचत होगी। संशोधन के लाभ

15 प्रतिशत भूमि के नियमितिकरण अनुमति से उद्यमी अपनी इकाइयों बुनियादी ढांचे को बेहतर बना सकेंगे। इससे उत्पादकता और कार्यक्षमता में बढ़े होगी। औद्योगिक क्षेत्रों में आवास विवेक्षा शुरू होने से श्रमिकों को सुरक्षित र सुविधासम्पन्न आवास मिलेगा। यह की कार्यक्षमता और जीवन स्तर को बढ़ाने में मदद करेगा। अनुकूल नीतियों के कारण छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विशेष को बढ़ावा मिलेगा। यह विशेष से छोटे और मझोले उद्यमों के लिए प्रभावी होगा। श्रमिक आवास और पंचोद्योगिक विस्तार से स्थानीय स्तर पर नगरीय के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा।

छत्तीसगढ़ – मुख्यमंत्री

युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने का स
प्रभाव पड़ा है।
मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी द
राज्य सरकार वर्ष 2026 तक छत्तीसग
नक्सल मुक्त बनाने के लिए कटिबद्ध है
बस्तर को भारत के प्रमुख पर्यटन के
रूप में विकसित करने की दिशा में ते
काम हो रहा है।

मुख्यमंत्री सायन ने यह भी आश्वासन दिया कि छत्तीसगढ़ केंद्र सरकार के अंतर्गत निर्देशों का पूरी निष्ठा से पालन करेगा। देशभर में कानूनी सुधार की इस पहल में प्रभावी ढंग से लागू करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा।

नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अत्यंत गंभीरता के साथ कार्यवाही कर रहे हैं। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कार्यवाही की सहाजता करते हुए कानूनी मंत्री ने शीघ्र रूप से कानूनों को राज्य में प्रतीतिष्ठ लागू करने पर बल दिया।

औद्योगिक क्षेत्रों में आवास सुविधा से 1
की क्षेत्रों पर जनसंख्या का दबाव कम 1
का, क्योंकि श्रमिकों को औद्योगिक 1
में भी रहने का विकल्प मिलेगा। 1
गौरतलब है कि पहले औद्योगिक 1
इयों को पड़े पर दी गई भूमि का 1
कोण केवल विशिष्ट औद्योगिक 1
विधियों के लिए करना होता था 1
औद्योगिक उपयोग, जैसे कार्यालय 1
न या कर्मचारी सुविधाओं के लिए, 1
मति लेना जटिल और समय लेने 1
था। नए नियम के तहत, 15
स्थान भूमि को बिना किसी जटिल 1
न्याय के नियमित करने की अनुमति 1
है। यह उद्यमियों को पर्यावरण 1
मजबूत करने और बुनियादी ढांचे 1
हरण के लिए, एक इकाई अब इस 1

पति ने धारदार
की पत्नी

गरियाबंद-रायपुर (आरणएस)
जिले के छुरा थाना क्षेत्र के आवासस्थानों में मोहल्ला देवे आज सुबह एक विस्फोट के बाद दो महिला मर गईं। 30 वर्षीय महिला बिसनी मार्कंडेय की हत्या उसके पूर्व पति गोपी मार्कंडेय के धारदार हथियार से कर दी। हत्या के बाद आरोपी युवक स्वयं छुरा थाने पहुँच गए और आत्मसमर्पण कर दिया। थाना प्रभारी दिलिप मेथ्राम ने बताया कि आरोपी युवक महासमुंद जिला का रहने वाला है। करीब 40 वर्ष पूर्व दोनों का सामाजिक रूप से तलाक हो चुका था। लेकिन इसके बावजूद गोपी, बिसनी का दोबारा अपने साथ रखना चाहता था। इस बात को लेकर अक्सर विवाद हो रहे रहते थे। मृतका दो बच्चों की माँ थी।

निशित भूमि पर कर्मचारी कल्याण
प्रशिक्षण सुविधा, या गोदाम बना
नी है।
नौऔद्योगिक क्षेत्र अक्सर
ण या अर्ध-शहरी इलाकों में स्थित
हैं। श्रमिकों के लिए आवास की
रहती है। इससे श्रमिकों को लंबी
यात्रा करनी पड़ती है, जिसका असर
उत्पादकता पर पड़ता है। संशोधन
है, औद्योगिक इकाइयाँ अब अपने
में या आसपास श्रमिकों के लिए आ
स बन सकती हैं। यह सुविधा न
श्रमिकों के लिए लाभकारी होगी,
उद्यमियों को भी स्थिर और
त कर्बलब उपलब्ध कराएगी।
नौऔद्योगिक विभागों का मानना है
है संशोधन छत्तीसगढ़ को निवेश के
और अधिक आकर्षक बनाएगा।

हथियार मारकर की हत्या

और बच्चों के साथ ही आवासपासा में रहती थी।स्थानीय लोगों के अनुसार, गोपी पहले ही महिला के घर आया-जाता था और उनको बीच कहा-सुनी होती रहती थी। सोमवार को हुई बहस के बाद आरोपी ने अनामक महिला पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।घटना की सूचना मिलते ही दुरा पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और इलाके को सील कर दिया।जॉर्जिया के भी बुलाया गया है, जो साक्ष्य एकत्र करने में जुटी है। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस दर्दनाक घटना से क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है।

जमीन पर कब्जा, खून से पत्र लिखने से लगाई मदद की गुहार

बलित्त उसके साथ दुव्यवहार भी किया गया. इसकी शिकायत उसने कलेक्टर, एसपी से लेकर जिले के सभी बड़े अफसरों से की थी पर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उसने जुल्म की कहानी खानू से लिखकर राष्ट्रपति के नाम स्पीड पोस्ट किया है.आज जिले में नए कलेक्टर भगवान उईके ने तत्कालीन कलेक्टर दीपक अग्रवाल से भार ग्रहण किया है. इधर जब भार ग्रहण की प्रक्रिया चल रही थी उधर ओम बाई ने खुन से पर लिखा और स्पीड पोस्ट की, इसकी तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो रही है. पीडिता को अब नए कलेक्टर भगवान से उम्मीद है.पीडिता ओम बाई का एक रोट हेतु वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उसने बताया किस तरह उसके पुरखों की जमीन पर किया गया. कब्जा के दरम्यान पूर्वजों को तोड़ा गया. इस दरम्यान महिला साथ बार-बार अपमान जनक व्यवहार जाता रहा. इस मामले में प्रशासन की छुड़ा तहसीलदार ने दलील दी है कि तीन साल से चल रहे जमीन विवाद में साराड के पक्ष में फैसला आया है. र अनधिकृत के मुताबिक उसे कब्जा र गया है. कब्जा दिलाकर हम लौट आ हमारी गैर मौजूदगी में पक्षकार ने क्या कैसे मठा को तोड़ा गया, इसकी जा नई नठ

मी से करवाई पति की हत्या

पेट्रोल-डीजल का अवैध भंडार

पुलिस ने 33 वाहन चालकों से 9900 रुपए जुर्माना वसूला

**बलौदाबाजार-भाटापारा ।
आरणएस**

जिला बलौदाबाजार-भाटापारा
पुलिस द्वारा आपरेशन विद्यार्थी
तहत यातायात नियमों का उल्लंघन
करने वाले वाहन चालकों पर सख्त
करवाई लगातार जारी है। आज दिनांक
20.04.2025 को दोपहरिया वाहन
में तीन सवारी चलने वाले 33 वाहन
चालकों पर कार्यवाही कर 99 सख्त
समन शुल्क किया गया वसूला।
मार्च 2025 में दोपहरिया वाहन में
सवारी बैठाकर वाहन चलाने वाले
कुल 3071 प्रकरण में 78,94,313
समन शुल्क किया गया है वसूला।
बलौदाबाजार-भाटापारा यातायात

 SJU - Contact Us
S...

पुलिस द्वारा आपोशन विश्वासके तहत यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार सख्ती से कार्यवाही की जा रही है, साथ ही जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, सुगम एवं सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था के लिए, यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों पर सख्त कार्यवाही करने हेतु यातायात पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 20.04.2025 को यातायात पुलिस द्वारा सड़क मार्ग में दो-पहिया वाहन में तीन सवारी, चलने वाले चालकों पर सख्त कार्यवाही किया गया है। यातायात पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान में दोपहिया वाहन में तीन सवारी चलने वाले 33 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही कर 29900 समन शुल्क वसूल गया है। इस वर्ष 2025 में दोपहिया वाहन में तीन सवारी बैठाकर वाहन चलाने वाले कुल 3071 प्रकरण में 78,94,300 समन शुल्क वसूल किया गया है। जिला बलौदाबाजार-भाटपारा यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता एवं यातायात नियमों के पालन हेतु सख्ती से लगातार कार्यवाही की जा रही है। पुलिस आत नागरिकों से अपील करती है कि आप सभी यातायात के नियमों का पालन करें एवं जिले में सुगम एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था के लिए आप पुलिस नियमों का सदैव पालन करें। पुलिस आपकी सेवा एवं सुरक्षा हेतु सदैव तत्पर है।

Tel. +91 9301915303 E-mail ID- sjunior29@gmail.com
Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

प्रकार की व्यापक

गठनसमूहों की स्वीकृति में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे स्वीकृति प्राप्त करने से मान्यता प्राप्त है, कि 5526 है, तथा समर्पण हेतु नं० 33019/53/303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं तीव्रतम प्रकाशित श्री प्रकाश (अधिकृत, माननीय उच्च न्यायालय), एवं निर्देशित कोर्ट के सदस्यों को श्री.जी.एम., श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, राहुदेव प्रभु एवं शानन को प्रकाशित प्रमाणित किया, और कला की प्रत को प्राप्त सामाजिक अन्वेषण अथवा मानवाधिकार के प्रत्यक्ष होने पर, उसे प्रतिक्रिया में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न मन्त्रालयों पर प्रत आसीत एवं सार्वजनिक व्यक्तियों के और प्रत्यक्ष किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बन्धी कार्य क्षेत्र में लेकर वेल्फेयर, गरीब, परिवारिक, विधवाओं लिए कार्य किया जावेगा।

संघ का उद्देश्य स्वीकृति प्राप्त प्रदेश के समस्त जिलों एवं लोक क्षेत्र में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा हेतु जागरूकता बढ़ाना करना है। संघ शास्त्रांत एवं अनुसूचित वर्ग शिक्षा के क्षेत्र में मानवाधिकार के संघर्ष में प्रचार फैलाना है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं लोक क्षेत्र पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना और उनमें संघ के द्वारा अधिकारिक नियुक्तियों की जावेगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फर्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध

पाण्डित्य व्यक्ति को समस्याओं को सुनना, अवगति लेना तथा पाण्डित्य को न्याय दिलाने के लिए अवगत साधन एवं जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पाण्डित्य व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

अपने मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु के लिए भारतीय संविधान के तहत विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित अपने अधिकारों से सम्पर्क कर सकता है।

व्यापन संरक्षण एवं पर्यावरण तथा सम्बन्धी वेतना हेतु भी जागरूकता ताने का प्रयास कर रहे।
अदालत प्रदेय में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, अतिवाहिरियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में सर्वोच्च न्यायालय के कार्यक्रमों को इस तरह समर्थित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीछिए को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में तस्वे देगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जाएगी।

मानव सभ्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं शासकों में विभिन्न पद्य पर आजीवन तक पीछिए को परेशानी को आसानी से पहुँचाना या सकना हेतु स्वं शासन एवं शासकों में विभिन्न महत्वपूर्ण पद्य पर आजीवन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीछिए को न्याय दिताने में समस्त श्म की कोशिशें करेंगे।

सर्वोच्च न्यायालय एवं समाजिक विकास से सम्बंधित दिरांक कार्यक्रम किए जाऐंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली वार्ता अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य और गैरसरकारी संस्थाओं से तथा मिलकर काम किया जाएगा।

विश्व कृषिनीतियों को दूर करने के लिए कार्यक्षमता का आवेोजन भी करेगा। संघ देश के भूते बिसरे हुए मलिन विश्वनीतियों के समान श्म भी आवेोजित कराएगा।

www.nyaysakshi.com

दा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि
न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

U Join SJU Join SJU Join SJU

SJU - Contact No. +91 9301915303

E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

अधिकार की व्यापक तक

Join SJU

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन ने मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नुं 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लोगल एडवाइजर श्री श्रीराम श्रीवास्तव (अधिकार, माननीय ऊच्च-न्यायाध्या), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कृपे श्री.बी.महेश, श्रीमती ऐनता श्रीवास्तव, श्रीमती उमनी गुरुनन्द एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कथ वित्त संघ के पास सामाजिक-अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण एवं पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हस्त में लेकर वेतलहल, गरीब, परिवर्तक, विधवाओं के अघात के लिए कार्य किया जावेगा।

आवश्यकता

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उन्मेष संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियों की जायेगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके द्वारा संघ के द्वारा निष्पादित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विभिन्नतरा एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्त हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित इस संघ में सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

पवित्र
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी वेनना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-अनुसूचितों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक ढंग के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संवैधानिक किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्त हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न एवं पर आसीन तक पीड़ित की परेशानियों को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण एवं पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता की करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास के सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जायेगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, लोककरी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कृषिप्रियों को दूर करने के लिए कार्यक्षमता का आवेदन भी करेगा। इस हेतु के मूले विस्तरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेंगे।

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU